SHRI J. M. BISWAS: What the Hon. Speaker said this morning does not debar Government from coming forward with a statement.

---

**14.26 hrs.**

## RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF PRESS COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE

## AND

## PRESS COUNCIL (AMENDMENT) BILL—*contd.*

**श्री यशपाल सिंह (देहरादून)** : सभापति महोदय, मैं उन सब मेम्बरान का बड़ा मशकूर हूं, जिन्होंने मेरे इस रैज़ोल्यूशन के हक़ में, या इस के खिलाफ, अपने खयालात का इजहार किया। हम में जो इख्तलाफात हैं, वे खयाली इख्तलाफ़ात हैं। हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। भगवान् महावीर स्वामी ने कहा है कि जो तुम्हारा विरोध करता है, वह तुम्हारा सब से बड़ा मित्र है, जिन लोगों ने मेरे इस रेजोल्येशन की मुखालिफ़त की है, उन का भी मैं ममनूने-एहसान हूं, क्योंकि उन्होंने रास्ता दिखलाने की कोशिश की है।

यह सरकार मुतवातिर पन्द्रह सालों से वादा कर रही है कि मानोपली खत्म होगी, लेकिन वह खत्म नहीं हुई है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मन वचन कर्म की एकता नहीं होगी, तो देश कभी उन्नति नहीं कर सकेगा। आज मन वचन कर्म की एकता नहीं है।

हम अपने कांस्टीट्यूशन में यह एलान कर चुके हैं कि हमारी राजभाषा, स्टेट लैंग्वेज हिन्दी है। लेकिन हम समाचार भारती को पचास हजार रुपये सालाना देते हैं और इंगलिश एजेन्सी को पचास लाख रुपये सालाना देते हैं। हम अपनी मातृभाषा के लिए अंग्रेज़ी के मुकाबले में सौवां हिस्सा खर्च करते हैं। कौन है, जो कांस्टीट्यूशन के इस एलान को, उस में किये गये वादे को, पूरा करेगा? इस के लिए आसमान से तो लोग नहीं आयेंगे। यह काम हमें ही करना होगा।

हम विरोधी नहीं हैं। "विरोधी" शब्द इंगलैण्ड का दिया हुआ है, यूरोप का दिया हुआ है। हम आपोज़ीशन में नहीं हैं। हम इन लोगों के सच्चे हितैषी हैं, सच्चे मित्र हैं। फारसी में मकौला है: "दोस्त आं बाशद कि मुआयबे दोस्त, हम चो आईना रोबरू गोयद", अर्थात् सच्चा मित्र वही है, जो अपने मित्र के दोषों को दर्पण की तरह सामने रख दे। हम ने इस बात का वादा किया है कि हम इस देश में हिन्दी को लायेंगे। लेकिन कौन उस को पीछे ढकेलता है? यह सरकार उस को पीछे ढकेलती है। अगर मैं सरकार को उस की ड्यटी याद न दिलाऊं, तो मैं अपने फर्ज़ से गिरूंगा। नीतिकार कहता है: "म किं सखा, साधु न शास्ति योऽधिपम् हिताम्न य: संशृणुते स किं प्रभु: अर्थात् वह सच्चा हितैषी नहीं, जो अपने बड़े को कठोरता के साथ सत्पथ न दिखला सके और बुजुर्ग भी वह सच्चा बुजुर्ग नहीं, जो प्रेम के साथ अपने हितैषी की शिक्षा न माने। अगर मैं सच्ची राय नहीं दूंगा, भले ही वह कड़ुवी लगे, तो मैं अपने कर्तव्य से गिर जाऊंगा।

हम सब का यह पहला फर्ज़ है कि हम गांधीजी के उन आदर्शों को जिन्दा रखें, जिन के कारण हमारा देश स्वतन्त्र हुआ था और अंग्रेज यहां से गये थे। आज प्रैस और आल-इण्डिया रेडियो में गाने वालियों और नाचने वालियों के जीवन-चरित्र दिये जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने देश के लिए सच्ची कुर्बानी दी, उन का जिक्र तक नहीं होता है। मैं बादशाह खां की टुकड़ियों में था, मैं बादशाह खां का सुर्खपोश हूं। मैं आज भी उन्हें संसार का महानतम पुरुष मानता हूं। मैं ने इस पार्लियामेंट को बीस दफा लिख कर दिया है कि मेरे मुताल्लिक

हू इज़ हू में लिखा जाये कि मैं बादशाह खां को भू-मण्डल का सब से बड़ा आदमी समझता हूं, मैं उन के साथ जेल में रहा हूं, मैं ने उन के साथ मिल कर अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष किया है, बग़ावत की है, लेकिन मुझे अफ़सोस है कि यह "हू इज हू" में नहीं लिखा गया।

आप को याद होगा कि जब अन्ग्रेज़ ने निहत्थे हिन्दुस्तानियों पर गोली चलाने का हुक्म दिया था, तो चन्द्रसिंह गढ़वाली ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया था। उस ने कहा था कि पहले इन निहत्थे लोगों के हाथ में राइफ़ल दो। उसके बाद हम गोली चलायेंगे। अंग्रेज़ ने उस को, और उस की पूरी बटैलियन को, 26–26 साल की सज़ा दी थी। हम देखते हैं कि न चन्द्रसिंह गढ़वाली का, न उस की बैटेलियन के कैपटेन या मेजर का, न किसी इनचार्ज का जीवन-चरित्र प्रैस में दिया जाता है। कोई रेडियो के ऊपर उन का जिक्र नहीं आता। हम लोग अगर आज इस आदर्श से गिरेंगे तो कौन इस आदर्श को पूरा करेगा? जय और पराजय आती है, संसार के अन्दर शिकस्त आती है, फतेहयाबी आती है लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि देशभक्तों को दुनिया भुला दे। जो हमारी आजादी, के फाउंडर्स हैं, मैं आज भी आप से अर्ज़ करता हूं कि मैं बादशाह खां को संसार का महानतम पुरुष समझता हूं :

वे और होगे भिसले बुलबुल आशनाए रंगो बू
हम ने दामन से न छोड़े फल मुरझाने के बाद।

लेकिन सरकार क्या कर रही है? उन की याददाश्त के लिए सरकार क्या कर रही है? गांधी जी के दरिद्रनारायण की सेवा के लिए क्या कर रही है? इस प्रैस कौंसिल आर्डिनेंस में गांधी जी के आदर्शों को जिन्दा रखने के लिए, समाजवाद को जिन्दा रखने के लिए, इसमें एक भी शब्द नहीं है। मेरी आप के द्वारा गुजराल साहब से यह प्रार्थना है कि इस बिल को काम्प्रीहेंसिव करें जिस से हमारा समाजवाद, हमारी भारतीयता, गांधीवादी, जिन्दा रह सके। मैं उन सब दोस्तों का मशकूर हूं जिन्होंने मुझे याद दिलाया खास कर के प्रकाश वीर शास्त्री जी का कि समाचार भारती एक ऐसी एजेंसी है जो भारत की प्रत्येक भाषा में समाचार प्रसारित करती है। मैं सब का मशकूर हुं जिन्होंने इस में भाग लिया और मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी हाउस में वादा करें कि किस तरह से हमारा देश चलेगा, कैसे हमारे आदर्श जिन्दा रहेंगे और गांधी जी की आत्मा को हम लोग प्रसन्न कर सकेंगे।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"This House disapproves of the Press Council (Amendment) Ordinance, 1969 (Ordinance No. 5 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 30th June, 1969."

*The motion was negatived.*

**श्री यशपाल सिंह** : अगर हमारे मंत्री जी वादा करें कि देशभक्तों के लिए और गांधी जी की मर्यादा के लिए एक काम्प्रीहेंसिव बिल वह लाएंगे तब तो मैं वोट नहीं कराऊंगा

**सभापति महोदय** : वह हो चुका। उस पर मत लिया जा चुका है।

The question is:

"That the Bill to amend the Press Council Act, 1965, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

*The motion was negatived.*

**Clause 2**—(Amendment of section 5.)

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause-by clause consideration of the Bill.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Madhubani): Sir, I move:

**Page 1, line 14—,**

[Shri Shiva Chandra Jha]

*"for* "31st day of March, 1970" (1).

*substitute*—

31st day of December, 1969".

Page 1, line 16,—

*for* "31st day of March, 1970." *substitute*—

"31st day of December, 1969." (2).

MR. CHAIRMAN: SHRI DAR.... Absent.

**श्री शिव चन्द्र झा** : सभापति जी, मेरा संशोधन है कि जहां पर चेयरमैन और दूसरे मेम्बरों का समय बढ़ा कर जुलाई से मार्च, 1970 करने की बात है उस जगह में चाहता हूं कि 31 दिसम्बर, 1969 तक ही उस का समय बढ़ाया जाय। इस की वजह यह है जैसा कि मैं ने उस दिन कहा कि प्रैस कौंसिल इनएफेक्टिव है उस मकसद को हासिल करने में जो मकसद उसका निर्धारित किया गया है। वह एक खिलौना मात्र हो गया है सरकार का। उस ढांचे में हकीकत में जो प्रेस का काम होना चाहिए वह काम नहीं होता है, न वह बढ़ पाता है। आज के अखबारों में आप ने देखा होगा कि प्रधान मंत्री ने कहा कि हिन्दुस्तान के अखबारों ने राष्ट्रीयकरण की बात को ठीक से सामने नहीं रखा और जो यह लहर चल रही है इस का समर्थन यह अखबार नहीं करते। बहुत हद तक मैं कहूंगा कि बात दुरुस्त . । यह निहित स्वार्थ के अखबार हैं। वह नहीं चाहते कि कल्याणकारी राज्य की ओर कदम बढ़ाया जाये। लेकिन जब प्रधान मंत्री यह कहती हैं तो हैरानी होती है कि क्योंकि निहित स्वार्थ के अखबारों की वकालत करने वाले भारतीय सरकार के राज्य सूचना मंत्री, यह हजरत खुद उस रूप में प्रैस को नहीं देखना चाहते जो कि हमारे संविधान का आदर्श है, जो हकीकत में प्रैस स्वातन्त्र्य का रूप है। इसीलिए प्रैस स्वातन्त्र्य के लिए लाजिम हो जाता है कि पहले यह जो राज्य मंत्री हैं इन को मंत्रि-मण्डल से निकाला जाय, इन से स्तीफा दिलाया जाय, यह निहित स्वार्थ वालों की वकालत करते हैं दूसरी बात रात रेडियो पर मैंने प्रेस कौंसिल के जो हैड हैं उन का वक्तव्य सुना। गोष्ठी में बोल रहे थे। उन का वह भाषण सुनने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि यह प्रैस कौंसिल जो कल डिजाल्व होनी चाहिए वह आज ही डिजाल्व कर दी जाये। यह खिलौना बन गया है।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि फाइनेंस कमीशन जो है इस ने ऐडवर्टाइजमेंट पर जो टैक्स लगाने की बात कही है और उस को शायद सरकार मान रही है, उससे प्रैस स्वातन्त्र्य बढ़ने वाला नही है। वह टैक्स आन नालेज है। बीमारी का इलाज सही रूप में न हो कर उलटे रूप में होने जा रहा है। और इन सभी के मुतालिक न प्रैस कौंसिल ने कोई काम किया है न करेगी, यह निर्विवाद है। अतएव इस का समय इतना न बढ़ाया जाय। 31 दिसम्बर तक समय बढ़ाया जाये और इस के बाद इस को डिजाल्व कर दिया जाये। इसीलिए मैं यह संशोधन चाहता हूं।

**श्री मधु लिमये** (मुंगेर): अध्यक्ष महोदय यहां पर घोषणा की गई है कि नये प्रैस कमीशन का निर्माण किया जायेगा। तो इस वक्त केवल नया प्रेस कमीशन कायम कर के जो बीमारियां हैं उन को दूर नहीं किया जा सकता है। इस वक्त हमारे प्रैस के ऊपर दो बड़े संकट हैं। एक सरकारी नियन्त्रण का और दूसरा बड़ी पूंजी के नियंत्रण का। कभी-कभी एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मंत्री महोदय बड़ी पूंजी के नियंत्रण की तो चर्चा कर देते हैं लेकिन उन के स्वयं की ओर से जो नियंत्रण सारे अखबारों पर रखा जा रहा है और उस से जो प्रैस की स्वतन्त्रता खत्म हो रही है क्या उस की ओर भी ध्यान दिया जायगा? मैं ने यहां पर एक व्यक्ति पूजा,

परसोनालिटी कल्ट का सवाल उठाया था और मैंने कहा था कि हिन्दुस्तान के अखबारों में यह प्रधान मंत्री की ताईद करो यह सारे इश्तिहार छपे कैसे? आज मैं राज्य मंत्री से सीधा जवाब चहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि जब कभी अखबारों के विज्ञापन या एडवर्टाइज़मेंट दिए जाते हैं तो जिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के द्वारा यह विज्ञापन मिलते हैं उस का नाम उस पर होना चाहिए। लेकिन इस विज्ञापन पर नाम है स्पान्सर्स बाइ ए ग्रुप आफ यंग बिजनेस एग्जीक्यूटिव्ज़ यह लिखा है । तो क्या वजह है कि ऐडवर्टाइज़िंग एजेंसी का नाम इस इश्तिहार में नहीं छापा गया? किस एजेंसी के द्वारा यह विज्ञापन मिला है इस का माननीय मंत्री जी खुलासा करें।

दूसरी बात क्या यह सही नहीं है कि जो इश्तिहार होते हैं उन के बारे में एक परिपाटी है कि राजनैतिक नेताओं के चित्र, उन की तस्वीरें उस में नहीं छापी जायेंगी? इस के बारे में मुझको पता लगा कि बम्बई के टाइम्स आफ इंडिया ने पूछा कि यह विज्ञापन छपने के पहले कि इस तरह की परिपाटी है कि नेताओं की तस्वीर नहीं दी जाती है तो क्या प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो से हम को इस तरह की अनुमति मिलेगी? यह मामला इन के ब्यूरो के पास आया और मुझे पता चला है कि प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो ने कहा है कि तस्वीर होते हुए भी यह विज्ञापन आप दे सकते हैं। तो इस बात का भी मैं खुलासा चाहता हूं। फिर किस मुंह से आप प्रैस स्वातन्त्र्य की बात करेंगे जब आप में आलोचना सहन करने की शक्ति नहीं है, टीकाटिप्पणी सहन करने की शक्ति नहीं है? इसलिए मैं बहुत गम्भीर चेतावनी देना चाहता हूं--आज पी०टी०आई,० समाचार भारती, यू०एन०आई० यह एजेंसियां दिन प्रति दिन सरकार के अनुदान पर निर्भर होती चली आ रही हैं । नतीजा यह होगा कि उस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन कीं मांगों के बारे में, उन की स्वतन्त्रता के बारे में कोई विचार नहीं होगा। अन्त में समाचार भारती के बारे में मैं एक वाक्य कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। समाचार भारती के कर्मचारियों की जो शिकायतें हैं उन के बारे में मैं मंत्री महोदय को लिख चुका हूं। समाचार भारती की हालत अच्छी नहीं है। सरकार ने काफी रुपया करीब-करीब 19 लाख रुपया तक देने का वायदा किया है। तो ऐसी हालत में क्या वजह है कि समाचार भारती का काम ठीक तरह नहीं चल रहा है? जो नियुक्तियां की जाती हैं उस में कर्मचारियों को बताया नहीं जाता है कि उन की सेवा की शर्तें क्या होंगी, उन्हें किस ग्रेड में रखा जायगा और जिस ढंग से यह खबरें वगैरह प्रकाशित की जाती हैं, अध्यक्ष महोदय समाचार भारती का विदेशों में कोई प्रतिनिधि नहीं है लेकिन आल इण्डिया रेडियो से खबरें ले कर अपने नाम से प्रसारित करने का काम किया जाता है। मेरे पास इस के सुबूत हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं सदन के टेबल पर रखने के लिये तैयार हूं। क्या मंत्री महोदय इस चीज़ की भी जांच करेंगे कि सरकार जब इन एजेन्सियों की मदद कर रही है, तो उस का नतीजा यह होता है कि कर्मचारियों की स्वतन्त्रता, लिखने की स्वतन्त्रता या तनख्वाहों आदि की सुविधाओं की शर्तें--इन के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बल्कि सरकार के गीत गाकर ये लोग अपना गुजर करते हैं। इस लिये मेरी प्रार्थना है कि अगर सचमुच आप प्रैस की स्वतन्त्रता चाहते हैं तो केवल नये प्रैस कमीशन की नियुक्ति से काम नहीं बनेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको खुलासा करना पड़ेगा।

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur): The Press Council must act as a united body and raise its voice against any attempt to intimidate and pressurize the press. Actually freedom of press constitutes the essence of democracy; it is one of the most cherished freedoms and the press assists in the

(Shri S. S. Kothari.)

crystallisation of ideas and formulation of public opinion. But, certain dark clouds appear on the horizon in the form of attempts to intimidate the press and exercise undue influence in order to compel the press to toe a particular line. Here I would like to mention the attempt that was made to intimidate a leading paper in Connaught Circus. One of the hon. members of this House led the procession and burnt copies of the *The Statesman*. I had a talk with him in the Central Hall and I was told that he did not burn the building but only burn the newspaper. I told him, whether he burnt the paper or he burnt the building, morally it amounted to the same thing. This is an attempt to intimidate the press; this is something which must be resisted if democracy is to exist.

My second point is this. The press in India has attained maturity. It is not going to be subdued by any such attempt to burn papers or building or ransack furniture or office. It is for the Government to give adequate and necessary protection to the press, where it is necessary. But a greater danger appears when the Government itself tries to pressurize and intimidate the press. In an editorial in one of the leading papers, it was stated that, on bank nationalisation, they resisted 'intense pressures' from the Government to toe a certain line and not to be critical of bank nationalisation or Government actions. If that is done, I would submit that it amounts to a grave danger to the freedom of press and various other freedoms in this country.

My final point is this. Attempts are also made to bring the editors of certain newspapers under the influence of the Government. Sometimes we find that that influence does have an effect and Opposition members are sometimes blacked out in certain papers. If that happens and if the Government takes initiative in influencing editors, then it is something which is reprehensible and it must be opposed at all costs if the press is to be free and if democracy is to exists in this country in the shape in which we want it to exist.

**सभापति महोदय :** मुझे सदन से एक बात कहनी है, हम लोग टाइम के बारे में काफ़ी एक्सीड कर गये हैं, इसलिये मेरा आप सब से अनुरोध है कि कम से कम समय लें, केवल प्वाइंट्स ही रख दें ताकि मिनिस्टर साहब उनका जवाब दे सकें ।

**श्री बलराज मधोक** (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, प्रेस कौन्सिल का उद्देश्य इस देश के अन्दर प्रस को आज़ाद रखना है, उसके ऊपर देश हित में जो नियंत्रण हो सकता, केवल उसी को रखना है । परन्तु हम देखते हैं कि जैसा और मदों में हो रहा है—मर्ज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की । प्रेस के मामले में भी जितना प्रेस की आज़ादी की चर्चा करते हैं, उतनी ही प्रेस की आज़ादी को कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा देश एक लोकतन्त्र है, जिसमें प्रेस की आज़ादी आवश्यक है । जहां पर प्रेस आज़ाद नहीं है, वहां लोकतन्त्र नहीं हो सकता । लेकिन इसकी जिम्मेदारी केवल अपोज़ीशन पार्टियों पर नहीं, केवल प्रेस के मालिकों और एडिटरों पर नहीं, इसकी जिम्मेदारी सब से अधिक उनकी है जो लोकतन्त्र के द्वारा राज करते हैं । परन्तु हम क्या देख रहे हैं । प्रधान मंत्री बोलती हैं तो कहती हैं कि प्रेस वाले गड़बड़ कर रहे हैं, सूचना मंत्री बोलते हैं—तो कहते हैं कि प्रेस वाले गड़बड़ कर रहे हैं । क्या गड़बड़ करते हैं ? कुछ बातों में सरकार की जो नीतियां हैं, उनका समर्थन नहीं करते । क्या प्रेस को सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार नहीं है ? अगर हमारा देश लोकतन्त्र न हो, एक तानाशाही देश हो, तब तो ठीक है, जो सरकार कहे, सभी प्रेस वही बात कहें, लेकिन जब तक हमारे देश में लोकतन्त्र है,

अगर कोई एडीटर यह महसूस करता है कि सरकार की नीति गलत है और वह उसके विरोध में कोई चीज लिखता है तो उसके बारे में नुक्ताचीनी की जाय—यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि जब प्रधान मंत्री और सूचना मंत्री की ओर से ऐसी बात कही जाती है, तो उनकी जो आफीशियल पोज़ीशन है, उस दृष्टि से उनका कहना एक प्रकार से नाजायज दबाव होता है। इसलिये प्रधान मंत्री और सूचना मंत्री को इस प्रकार के वक्तव्य देना बन्द करना चाहिये, क्योंकि यह प्रेस की आज़ादी में हस्ताक्षेप है ।

दूसरी बात—मैं यह कहना चाहता हूं कि आज प्रेस की नीतियों को नियन्त्रित करने का सब से बड़ा साधन एडवर्टिजमेन्ट्स हैं, क्योंकि सरकार उनको एडवर्टिजमेन्ट्स देने का सब से बड़ा साधन है तथा इसके द्वारा सरकार उनकी नीतियों पर कन्ट्रोल करने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य यह है कि एडवर्टिजमेन्ट्स भी कुछ ऐसे बड़े-बड़े समाचार-पत्रों के पास जाते हैं, जिनको हम एक तरफ कोसते हैं कि इनकी मोनोपली है, कन्ट्रोल है। हमारे तमाम एडवर्टिजमेन्ट्स का अधिकतर भाग इन्हीं बड़े बड़े साचार-पत्रों के पास जाता है। मेरी प्रार्थना है कि इन तमाम एडवर्टिजमेन्ट्स का प्रौपर डिस्ट्रीव्यूशन होना चाहिये। आज देश के अन्दर अधिकतर अखबार भारतीय भाषाओं के हैं, मगर अभी भी अधिकतर इश्तिहार अंग्रेजी अखबारों को दिये जाते हैं, अधिकतर नहीं दिये जाते तो भी उनकी रेशो अधिक है। मेरा कहना यह है कि अंग्रेज़ी समाचार-पत्रों के इश्तिहार कम हों और भारतीय भाषाओं के माचार-पत्रों को अधिक इश्तिहार दिये जायें। ताकि वे भी चल सकें, पनप सकें। आज समाचार-पत्र बिना इश्तिहार के नहीं चल सकते, डोल देकर आप कितने दिनों तक इनको चला पायेंगे।

आज मोनोपली की बात बहुत कही जाती है। आज का युग यंत्रों का युग है, कोई भी बड़ा अखबार चलाना हो, तो उसके लिये 40–50 लाख रुपया चाहिये। कोई अकेला व्यक्ति इसको नहीं चला सकता, इसी लिये बड़ी बड़ी कम्पनियां बनती हैं जिन के पास इनको चलाने के साधन होते हैं। बहुत से लोग उन साधनों को देश के बाहर से लाने की कोशिश करते हैं—यह बुरी बात है। इसलिये छोटे अखबारों को चलाना सरल काम नहीं है। इसी तरह से जो बड़े भारी समाचार पत्र बन गये हैं आज उनको चलाना है तो उनको छोटा नहीं किया जा सकता। आज अधिक से अधिक सर्कुलेशन 2 लाख है एक स्टेज ऐसी भी आयेगी जब एक-एक अखबार की सर्कुलेशन 20–20 लाख होगी इसलिये इनको छोटा करना बड़ा गलत काम होगा। हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि इन का सर्कुलेशन बढ़े। हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि अखबार की बात तो ठीक है, लेकिन एडीटर को फ्रीडम होनी चाहिये। मैं भी मानता हूं, कि एडीटर को फ्रीडम होनी चाहिये। लेकिन अगर एडीटर की नियुक्ति में फ्रीडम नहीं होगी, आपके दबाव से एडीटर नियुक्त होगा, तो वह एडीटर कभी आज़ाद नहीं होगा, उस का दिमाग़ तो बन्द होगा। आज हर जगह इस मामले में दबाव डाला जा रहा है और जिस ढंग से नियुक्तियां की जा रही हैं, उससे एडीटर आज़ाद नहीं हो सकते। आज कालीनाथ जैसे एडीटर नहीं हैं, जो बिल्कुल इण्डीपेंडटली चलते थे उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता था, लेकिन जब ऐसे एडिटर आयेंगे जिनकी नियुक्ति दबाव से होगी, तो फिर आप उनको आज़ाद नहीं रख सकते। इसलिये एडिटर की नियुक्ति के बारे में हमें विशेष प्रयत्न करना चाहिये। एडीटर की नियुक्ति के बारे में दबाव नहीं डाला जाना चाहिये, आज़ादाना ख्याल के एडिटर नियुक्त किये जयें।

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री** (श्री इ० कु० गुजराल) : इसके बारे में राय दीजिये, कैसे होना चाहिये?

**श्री बलराज मधोक :** वक्त बहुत कम है सभापति जी घन्टी बजा रहे हैं।

जहां तक मोनोपली का ताल्लुक है मैंने कई बार कहा है कि वास्तव में आज सब से बड़ी मोनोपली कम्यूनिस्ट पार्टी की है। 500 से ज्यादा अखबार एक पार्टी के अधिकार में हैं। उनकी एक विचारधारा है जिसके द्वारा वे जनता के विचारों को दूषित करना चाहते हैं। उस पार्टी के पास लाखों सोर्सेज़ हैं—उस की मोनोपली को आप तोड़ना नहीं चाहते हैं दूसरों की मोनोपली की बात करते हैं। कोई भी मोनोपली हो--ए हो बी हो सी हो--ए मोनोपली को बुरी कहें और बी और सी को कहें कि यह अच्छी है स्टेट की मोनोपली को अच्छी कहें—यह ठीक नहीं होगा। इस प्रकार की मोनोपली खत्म होनी चाहिये जिसमें स्टेट की मोनोपली तो सब से अधिक खतरनाक है प्राइवेट से ज्यादा खतरनाक है।

अन्तिम बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं—अभी यहां पर न्यूज़ एजेन्सी की बात कही गई है। इस समय हमारे यहां दो बड़ी न्यूज़ एजेन्सीज हैं—**पी० टी० आई०** और **यु० एन० आई०**। भारतीय भाषाओं के लिए समाचार भारती तथा हिन्दुस्तान समाचार। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो भारतीय भाषाओं की न्यूज़ एजेन्सीज हैं इन को आपने क्या प्रोटेक्शन दिया है इन की क्या स्थिति है। अगर आप चाहते हैं कि देश के अन्दर भारतीय भाषायें पनपें, उनके समाचार पत्र बढ़ें तो ऐसी समाचार एजेन्सियों की जो कमियां हैं उन्हें दूर कीजिये। उनको पूरा पूरा समर्थन देना होगा पूरा पूरा सहयोग देना होगा। समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार इन दोनों एजेन्सीज ने भारतीय भाषाओं के लिये बहुत काम किया है उन्हें विशेष रूप से समर्थन देना होगा।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे देश की कोई इन्टरनेशनल न्यूज़ एजेन्सी नहीं है। विदेशी समाचारों के लिये रायटर ए०पी०ए० या टास पर ही निर्भर करना पड़ता है। इसलिये आवश्यक है कि हमारी अपनी कोई इन्टरनेशनल न्यूज़ एजेन्सी हो। विदेशी समाचार जो हमारे यहां आते हैं वह भी हमारे करेस्पांडेन्ट्स ही भेजें क्योंकि रायटर ए०पी० ए० और टास द्वारा जो समाचार आते हैं वह कलर्ड होते हैं उनमें भारत के विचार नहीं होते हैं बल्कि उन देशों के विचार होते हैं जहां से कि वे आते हैं। इसलिये हमारे देश की कोई इन्टरनेशनल न्यूज़ एजेन्सी होनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं मंत्री महोदय उन पर अवश्य ध्यान देंगे।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : सभापति जी, कब्ल इसके कि मैं अपना समर्थन इसको दूं, मैं कुछ चीजें आपकी मार्फत मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। सब से पहले तो श्री बलराज मधोक जी ने जो कहा कि मोनोपली जो है वह कम्युनिस्ट पार्टी की है अखबारों पर, तो शायद वे इससे यह साबित करना चाहते थे कि मोनोपली टाटा की नहीं है, मोनोपली बिरला की नहीं है, मानोपली गोयन्का की नहीं है.....

**श्री बलराज मधोक :** मैंने ऐसा नहीं कहा।

**श्री स० मो० बनर्जी :** अगर ऐसा नहीं कहना चाहते तो फिर एक चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के ज्यादा अखबार हों लेकिन आर्गेनाइजर में जैसा हमने नियो जर्नलिज्म देखा है वैसा नियो जर्नलिज्म हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा। शायद करेन्ट से भी ज्यादा है।

**एक माननीय सदस्य** : ब्लिट्ज़ के बारे में क्या कहना है ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : हमारा कहना यही है कि ऐसे अखबारों को कन्ट्रोल किया जाये । जिस चीज़ को वे आर्गेनाइज़ करते हैं, हमको वही नहीं मालूम होता है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पहले कम्युनिस्ट अखबारों को पढ़ें और इतना एन्टी कम्युनिज्म न रखें । ..... **(व्यवधान)** ..... उसके बाद मैं समझता हूं अगर आप धीरज से पढ़ेंगे तो दिमाग़ साफ़ होगा—इतना मेरा विश्वास है । ..... **(व्यवधान)** ...

मैं दो चीजें कहना चाहता हूं । ... यह कि सदन में एक आश्वासन दिया गया था और अभी मंत्री महोदय जब बंगलौर या मद्रास गए थे तो उन्होंने कहा था कि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया का कारपोरेशन बनाया जायगा । इसके लिए प्रेस कमीशन की सिफारिश भी है । खुशकिस्मती से पी० टी० आई० के जो इम्पलाइज हैं उनको आल इंडिया समर्थन प्राप्त है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको उसमें सुधार लाना है तो उसको कारपोरेशन बनाना चाहिए । क्योंकि आज जैसा हम देख रहे हैं चाहे उनके चेयरमैन साहब हों, डायरेक्टर साहब हों या जनरल मैनेजर साहब हों, उनके सामने जब हम कोई मामूली और छोटी से छोटी चीज कर्मचारियों की ओर से रखते हैं—चाहे वह जर्नलिस्ट्स की बात हो, नान-जर्नलिस्ट्स की बात हो या अन्य कर्मचारियों की बात हो तो उनको इनकार कर दिया जाता है । पहले 6 परसेन्ट बोनस दिया गया लेकिन अब की मर्तबा वह नहीं दिया गया है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप एक कारपोरेशन में कन्वर्ट कीजिए । मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं । श्री वी० वी० प्रसाद का केस है । वे पी० टी० आई ० में सीनियर जर्नलिस्ट्स थे लेकिन उनको वहां से डिसमिस कर दिया गया । उनका कसूर यह था कि एज आनरेरी सेक्रेटरी, बरट्रेन्ड रसेल पीस फाउन्डेशन इन इंडिया, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था । इस पर उनसे कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो । मंत्री महोदय ने पार्लियामेंट के उस हाउस में जवाब देते हुए कहा है कि यह मामला वह देखेंगे और प्रेस काउंसिल देखेगी लेकिन प्रसाद साहब आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसको देखें । समाचार भारती के बारे में श्री मधु लिमये जी ने और मधोक जीने कहा है कि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है । इतनी खराब हो चुकी है कि उसकी मीटिंग्ज़ भी ठीक से नहीं होती हैं । श्री प्रकाश ने एक पत्र श्री फीरोज़ चन्द्र को लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है :

In this interval many meetings of the Board of Directors have been held of which such short notice was given time that I could not possibly attend them.

बाद में उन्होंने मायूस होकर कहा है :

I have not been attending the board meetings and it is embarrassing for me to continue to be the Chairman.

आप सोचिये कि इन जैसा व्यक्ति जो न केवल गवर्नर रह चुके हैं, राजनीतिज्ञ हैं बल्कि मैं कहना चाहता हूं साहित्य के जगत में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है—वे उसको छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि उसमें बहुत गड़बड़ी है जो ठीक नहीं हो सकती है ।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पी०टी०आई०को एक कारपोरेशन में कन्वर्ट किया जाये, सामाचार भारती को ठीक करना चाहिये ताकि उसमें जो गड़बड़ियां हैं वह दूर हो जायें । तीसरी चीज यह है कि जो मोनोपली है उसको खत्म किया जाये । फ्रीडम आफ दि प्रेस पर कोई भी अटैक नहीं

(श्री स० मो० बनर्जी)

होना चाहिये । झूठ के प्रेस अगर पनपेंगे तो हमारा देश समाजवाद की दिशा में जा नहीं सकेगा ।

**श्री जार्ज फ़रनेंडीज** (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, अखबारों की मोनोपली के बारे में, मालिकी के बारे में बहस चल रही है। मैं इस बात को मानता हूं कि इस समय पूंजीपतियों के हाथों में जितने अखबार हैं उनका बेजा इस्तेमाल किया जाता है लेकिन फिर भी मैं यह समझता हूं कि बहस में इस बात को भी मद्दे-नजर रखना चाहिए कि सिर्फ मालिकी अखबारों की किसकी है इतना ही नहीं बल्कि इन अखबारों का इस्तेमाल किस ढंग से किया जाता है, वह महत्वपूर्ण बात है। ..... (**व्यवधान**) ..... आज जो हम एक सिलसिला देख रहे हैं उससे हमें ऐसा लगता है कि सरकार के समर्थन में अगर कोई अखबार खड़ा होगा तो वह अखबार ठीक है लेकिन अगर किसी अखबार में सरकार के विरोध में कुछ भी बात आयेगी तो वह अखबार भी बहुत ही खराब है । आज सुबह प्रधान मंत्री की एक तकरीर मैंने पढ़ी । जो व्यंग चित्र निकालने वाले हैं उन पर भी गुस्सा कर रही हैं । यानी अखबारों में क्या क्या खबरें छप कर आईं, इस पर तो उनकी परेशानी है ही लेकिन अगर किसी कार्टून में भी उनकी तस्वीर जरा इधर उधर हो जाये, बाल कुछ ठीक ठाक न किये जायें तो उस पर भी गुस्सा व्यक्त करने के लिए प्रधान मंत्री पहुंच रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या अखबारों का इस्तेमाल सिर्फ सरकार, सरकार की नीति और "अवर लीडर" की तारीफ करने के लिए होना चाहिए ? अभी चन्द दिनों पहले हिन्दुस्तान के अखबारों में एक विज्ञापन आया— रैली बिहाइन्ड अवर लीडर । किस की ओर से ? ग्रुप आफ यंग बिजनेस एग्जीक्यूटिव्ज की ओर से ।

**सभापति महोदय :** इसका रेफेंस मधु लिमये जी दे चुके हैं ।

**श्री जार्ज फ़रनेंडीज :** आप जरा इसको सुनिये । किस तरह से अखबारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं उसका सबूत आपके सामने दे रहा हूं । 50 हजार रुपये से अधिक उस विज्ञापन पर खर्च हुआ । और यह रुपया किसी यंग बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने नहीं दिया बल्कि यह रुपया महेन्द्र एण्ड कम्पनी ने दिया । ..... (**व्यवधान**) ..... इस कम्पनी की तरफ से रुपया दिया गया और इंडियन सोसाइटी आफ एडवर्टाइजर्स जिसके जरिए से विज्ञापन दिये जाते हैं, इस विज्ञापन को निकाला गया लेकिन नीचे लिखा ग्रुप आफ यंग बिजनेस एग्जीक्यूटिव्ज । इस प्रकार कितना झूठ अखबारों के जरिए फैलाया जा रहा है एक व्यक्ति की तस्वीर को दुनिया के सामने पेश करने के लिए ..... (**व्यवधान**) ..... इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि महत्व इस बात पर नहीं देना चाहिए कि इस समय अखबार के कौन मालिक हैं बल्कि ज्यादा महत्व इस बात पर देना अखबारों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है । (**व्यवधान**) .... इस सरकार के अस्तित्व में और इस के स्वरूप में या इसकी तस्वीर में एक कौड़ी का भी फर्क नहीं आया है । यह सरकार एक साल पहले या एक महीने पहले जो थी वही आज भी है । लेकिन अखबारों का इस्तेमाल जरूर देश के लोगों को गुमराह करने के लिये किया जा रहा है कि समाजवाद की ओर देश चल रहा है । प्रधान मंत्री के मकान के सामने लोगों को इकट्ठा करो, वे कुछ चिल्लायें और प्रधान मंत्री कुछ कहें और फिर अखबार के जरिए लोगों को गुमराह करने का काम चले । अगर यही अखबारों की स्वतन्त्रता का मतलब हो तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है । इसलिए मैं बहुत ही नम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि मालिकी किसकी है, यह महत्व की बात जरूर है लेकिन अखबारों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यह उससे भी

ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आज देश में एक सिलसिला चला है कि सरकार के एक नेता, एक दल और एक नीति के पीछे सभी खड़े हो जायें। इस किस्म से लोगों को गुमराह करने के लिये अखबारों का इस्तेमाल किया जाता है यह बन्द करें और अखबारों में झूठे इश्तिहार देकर एक तस्वीर बनाने का प्रयास बन्द करें तथा कारटूनिस्टस लोगों को, और गरीब कर्मचारियों को धमकाने वाला तरीका जो आप लोग चला रहे हो, प्रधान मंत्री के दरवाजे के सामने ट्रकों में भर कर कुछ लोगों को लाकर खड़े करने का जो सिलसिला है इस सिलसिले को बन्द करें वरना यह बात आपके दल के लिये, इस मुल्क के लिये और प्रजातन्त्र के लिये खतरनाक होगी ।

15 hrs.

**सभापति महोदय** : श्री पीलू मोदी ।

**श्री कंवर लाल गुप्त** (दिल्ली सदर) : आप हमको भी बोलने देंगें ?

**सभापति महोदय** : देखिये, दो घंटा इस का वक्त था, लेकिन आप करीब तीन घंटे ले चुके हैं। थर्ड रीडिंग के वक्त देखा जायगा ।

**श्री मधु लिमये** : दो, दो मिनट दीजिये ।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : कम से कम पांच, पांच, मिनट का समय दीजिये ।

SHRI PILOO MODY (Godhra): Sir, for the last so many years, I have been rather concerned with our depleting freedoms. In the last few months, we have seen great inroads being made not only on our freedoms but also on our credulities. We have seen reports published which have been deliberately planted in newspapers. In fact, I have been going around saying, in the last three weeks, at least a few hundred lies must have been published deliberately in the press.

I cannot entirely blame the reporters and pressmen who have taken these reports to their offices, because I have known from personal knowledge that very often reports were given, information leaked out and statements made which were contrary to real facts. This process of gradual erosion on our freedoms started many years ago, but as a result of what happened during the last two or three weeks, it has taken on an accelerated tempo. At this stage, I would like to mention a particular conversation which was heard from a Cabinet Minister by several people present not far from where I am standing now. A Cabinet Minister of the Government of India was trying to impress upon his limited audience about how the press had now become very fair and very balanced in its view. He quoted an editorial written in the *Hindustan Times* and said, "See what a balanced editorial this is!" He went on to say that except for Frank Moraes "What has been published in the *Express* also is giving a very balanced view." An observer happened to point out, "What about the *Statesman?*" He said, "What can I do? The trouble with the *Statesman* is that they can stand on their own legs." I think a world of meaning can be implied in this slip on the part of this Cabinet Minister. I am afraid that this is the fact that we have all been subjected to. Sir, you have heard speakers before me complaining very bitterly and I will not make the same accusations. I think they have been rather eloquently made. But it is not only the press but also our airways that have been somewhat polluted recently. I can assure you, it was not through another nuclear explosion. This time it was purely by the verbiage that was fed into the air. Similarly on many other fronts. I feel our freedom has been eroded. I would like to take this opportunity of warning this House that unless we

set some rules and code of conduct about what is good Journalism, what is independent journalism and what is journalism uninterfered by the single largest and greatest authority and power that we are surrounded with—the Government of India—I think our fate and our future are rather dismal.

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga): Mr. Chairman, the function of an Ambassador is to lie in a foreign country about his own country for the good of his own country. Similarly, the function of the press is to lie in its own country about its own country for the good of its own country. Fortunately or unfortunately the press, which is the guide of the progress of the country, is failing in its duty because most of the newspapers are owned by big businessmen or political parties. So long as they are owned and managed by big business or political parties their primary function would be to sing the song of their owners. Therefore, unless the monopoly in newspapers is removed they cannot give expression to their independent opinion and thereby serve the nation. What the country today needs is independent opinion about many things which affect the interests of the country. For instance, the opposition consider it their function to oppose anything that comes from the government, whether it is right or wrong. In the same way, if the newspapers are owned by political parties, they would also function the same way. Therefore, in the interests of the country, the press, which is one of the instruments of freedom of expression, should be allowed to function freely and without any restrictions. If they are not given that freedom, then there is no use of talking about the fundamental rights of the citizens.

Then, if government make some investment in some papers or news agencies they should ensure that they are functioning well. For instance, I have been hearing complaints about *Samachar Bharati;* I do not know how far they are correct. Since a number of governments have invested money in this news agency, it is the duty and responsibility of the government to appoint a Managing Director or General Manager in the Board so that he can look after the interests of the government and the money that has been invested by the government. At the same time, he can ensure that some guidelines are formulated as to how it should function.

All the laws that we enact should be with a view to see that the Press Council enjoys the maximum freedom, uninterfered by any political party or businessmen.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMAION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): I am grateful to the hon. Members that on clause 2 so much debate has been initiated. Some points have been made which I would like to meet here. One of my hon. friends has asked me if we are giving substantial advertisements to Indian language papers or not, so far as advertisement goes. I will dispose of this point by saying that not only are we helping the small and medium newspapers but we are particularly helping the Indian language newspapers. 18.13 per cent of the total budget of the DAVP goes to Hindi papers and 37.98 per cent to other Indian language newspapers; in other words 56 per cent of the total budget of DAVP goes to language papers.

**श्री जार्ज फरनेन्डीज** : 45 परसेंट अंग्रेजी के अखबारों को जाता है ।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : अंग्रेजी डेढ़ परसेंट लोग जानते हैं, लेकिन आप अंग्रेजी के अखबारों को 45 परसेंट देते हैं ।

सभापति महोदय : आप लोग मंत्री जी को बोलने दीजिए । आप जब बोल रहे थे तो कोई नहीं बोला, इसलिए आप भी उनको बोलने दीजिए ।

SHRI I. K. GUJRAL: If there are any other points, I will deal with them during the third reading. The main point that I am trying to make is this. If there are more English newspapers and if they command more readership, I cannot help it. I can only assist them in two ways. Whatever Indian language newspapers come in, we shall be able to give them assistance in newsprint, in advertisement and we shall also provide facilities to them in any other way that they wish.

I have often stated here that we have evolved a policy for helping small and medium newspapers as far as it is possible. I am conscious of the fact that small and medium newspapers are almost predominantly Indian language newspapers. Therefore, if even today some percentage of the advertisment expense goes to English newspapers, the fault lies elsewhere. But I can assure the House to this extent only that we shall do our best to see that small and medium newspapers and Indian language newspapers get the maximum possible assistance.

Since I am talking of the Indian language newspapers, let me dispose of another point in this connection. A debate has been going on for some time in the form of discussions and at other times in the form of questions about *Samachar Bharati*. Shri Prakash Vir Shastri, an hon. Member of this House is a director of it. I think the day before yesterday he put across his point of view. I do see in the House that there are other points of view also. Government have been receiving a number of complaints about the working of the *Samachar Bharati*. It will be very unfair if I were to tell the House anything about what Government's reaction is. But I do feel that I must say one thing namely that the working of the *Samachar Bharati* does need looking into, and we are looking into it. More than that I would not like to say at this stage. But before I dispose of this item, I would like to say this that it is Government's intention and desire that Indian language news agencies must prosper, because if Indian language papers have to come up, then it is very essential that Indian language news agencies must also prosper. It will not be possible for Indian language newspapers to come up unless the two news agencies that we have also prosper.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : जब तक टेलीप्रिंटर हिंदी में नहीं बनेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा ।

SHRI I. K. GUJRAL: Since the hon. Member has raised the point, I might tell him that the Devnagari teleprinter has already come in.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : कितने आये? बहुत कम आये हैं ।

SHRI I. K. GUJRAL: I can only say this thing that it may be difficult for me to give the number, but as far as I know, and my colleague tells me, all the demands for the news agencies have been met and are being met. If there is a demand for more, then it will be met. Therefore, there should be no difficulty in developing Indian language news agencies. I have no objection if my hon. friend wants one in his house, if he is willing to subscribe to it.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): We can meet whatever demand comes.

SHRI I. K. GUJRAL: Shri Shiva Chandra Jha has mentioned that the Press Council has failed and has been

[Shri I. K. Gujral.]

ineffective and that I should resign because I am supporting the freedom of the press. I shall not say anything here except to say that if I have to resign for supporting the freedom of the press, not only shall I do so, but even if I have to lay my life for supporting the freedom of the press, I shall do so.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: There is a big difference between his concept and the Prime Minister's concept. यह मानना होगा। आप एक चीज की वकालत करते हैं, उन का दृष्टिकोण दूसरा है। इसलिए मंत्री महोदय इस्तीफा दें।

SHRI I. K. GUJRAL: I would request my hon. friend to be kind to us and to the Prime Minister when he says that I do not understand her mind but he does. I understand the Prime Minister's mind and what I am saying is her commitment. The main point that I am trying to make is this. (*Interruptions*). It is a normal habit with my hon. friend Shri Kanwar Lal Gupta to interrupt others and feel angry when others do the same, but I hope he will try to extend the same courtesy to me also.

We all have talked here of freedom of the press. Some friends have been upset about why the Prime Minister or I sometimes object to some writings in the press. The press in this country is free. So is the public opinion, and so is there freedom of speech. So is there freedom for all of us. If I therefore reply to the unfair criticism what is wrong with it? It will be a strange type of freedom of the press, if the press has a right to say what it likes, but we . . .

**श्री जार्ज फरनन्डीज** : बहुत फर्क है। आप बुली करते हैं और हम क्रिटिसाइज करते हैं। प्रधान मंत्री जो भी बोलते हैं That amounts to bullying.

SHRI I. K. GUJRAL: I can assure my hon. friend Shri George Fernandes, and I hope he will agree with me that the press in this country is strong enough not to be bullied either by him or by me. The main point is that the institution of press in this country has come to that strength that neither the Members of the Opposition nor the Government can bully them; not only that, but the press has a tradition that it was not bullied even by the British. Therefore, the question of anybody succeeding in bullying the press does not arise.

**श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या आपको याद है कि मोरारजी देसाई ने **टाइम्स आफ इंडिया** के साथ क्या किया था? आप भूल गये हैं कि उन्होंने **टाइम्स आफ इंडिया** से माफी मंगवाई थी जब वह एक छोटे से मुख्य मंत्री थे।

SHRI I. K. GUJRAL: I am not yielding.

MR. CHAIRMAN: If the hon. Minister is not yielding, how can the hon. Member go on?

SHRI I. K. GUJRAL: It sounds to me rather strange after the last four or five weeks' experience, that anyone should say that the press in this country is not free to criticise Government. It is rather odd. I think Government have faced a barrage of criticism from a particular section of the press—I would not name them. So, if the Prime Minister or any member of the Government talks to the public and explain their own point of view or the Government's point of view, I think we should also be permitted to have that much of freedom.

I was surprised and shocked when a lover of democracy like Shri George Fernandes came and said that demonstrations outside the Prime Minister's house should stop and that people should not go there and that people should not be allowed to go there.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं ने नहीं कहा। ऐसा मैं ने बिल्कुल नहीं कहा।

SHRI I. K. GUJRAL: He is a very strange trade union leader who would object to this. Let me finish what I am going to say. I am not yielding.

श्री जार्ज फरनेंडीज : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति जी, मैं ने यह नहीं कहा है . . . . . . . . . .

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): He is a fascist and he calls himself a democrat.

SHRI I. K. GUJRAL: My non. friend Shri George Fernandes claims to be a trade union leader . . .

SHRI GEORGE FERNANDES: I am one.

SHRI I. K. GUJRAL: And I respect him for that. Since I respect him for being a trade union leader, he should also learn to respect trade unions and when trade unions go and demonstrate and show their solidarity behind bank nationalisation, he should feel proud of them. I really felt sorry when he got up and said that these demonstrations should be stopped. These people for the first time had seen a ray of hope in the social changes that had been brought about (*Interruptions*). I do not mind if my hon. friend Shri Kanwar Lal Gupta keeps on howling and is also joined in by his friends from the Swatantra Party, because his party has been exposed as having no economic programme which stands for improving the lot of the people.

SHRI PILOO MODY: Are we discussing bank nationalisation now?

SHRI I. K. GUJRAL: A point has been made by my hon. friend Shri Madhu Limaye regarding Government control and big money control . . .

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : एक हमारी पार्टी है, जिस के पास प्रेस नहीं है और इतने दिनों से राज्य कर रही है और एक आप की पार्टी है जिस के पास प्रेस है लेकिन राज्य नहीं कर पाये।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : आप हिन्दुस्तान टाइम्स हम को दे दीजिए।

श्री स० मो० बनर्जी : टाइम्स ग्राफ इंडिया आप हम को दे दीजिए।

SHRI I. K. GUJRAL: My hon. friend Shri Madhu Limaye has talked about the desirability of implementing the recommendations of the First Press Commission. He has also asked why Government are thinking of appointing a second Press Commission. I would only say this that the idea of starting or setting up a second press commission is not to bypass the recommendations of the first Press Commission. The first Press Commission's recommendations have been implemented; some still remain to be implemented. As regards those that remain to be implemented, I can assure my hon. friend on behalf of Government that we shall endeavour our best to implement them and quickly too and not take time about them.

The only idea why we are thinking of a second Press Commission is that the dimensions of the problem have very much widened and intensified in the last 15 years. The press in this country has grown; public opinion has grown and reaction to each other has grown. I think, social implications have also changed to a degree. Therefore if a second commission sits and examines it afresh, no harm will come out of it but something good is bound to emerge from it and I think the Government will have a considered opinion on which to base its own policies.

He and some other hon. friends have also talked about some advertisement which appeared in some papers under the caption 'Rally round the Leader'. Naturally, it is not for

[Shri I. K. Gujral.]

the Government to reply to such a question. Some advertisements have appeared in the papers, paid by somebody. Who paid for it and why they appeared, is not within the cognisance of Government. Therefore Government is not supposed to reply to this.

**श्री मधु लिमये** : मैं ने यह जानना चाहा था कि जिस ऐजेंसी की मार्फत यह विज्ञापन आया क्या उस एजेंसी का नाम उस पर नहीं आना चाहिए था। जब एडवर्टिजमेंट के धंधे की यह परिपाटी है कि किसी नेता की तस्वीर नहीं छापी जाएगी तो ऐसी तस्वीर छापने की क्या इजाजत पी० आई० बी० से ले ली गई थी ?

SHRI I. K. GUJRAL: After my hon. friend asked these two questions, sitting here I got it checked up. Naturally, sitting here I cannot have more information than what is very brief; but whatever information I have been able to collect shows that Government's permission was neither asked for nor given. Therefore that point should be disposed of by this.

Publication of leaders' photographs or paintings is banned for commercial utilisation. But it is a point to be examined whether in an advertisement like this it is for commercial utilisation.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Ultimately, it is commercial.

SHRI I. K. GUJRAL: Ultimately, everything that strikes Shri Kanwar Lal Gupta is wrong. Everything that does not go in his interest . . . (*Interruption*).

SHRI PILOO MODY: Are you suggesting that the use of the Prime Minister's sketch is not permitted for the sale of soap but can be permitted for the sale of the Prime Ministership itself?

SHRI I. K. GUJRAL: My hon. friend, Shri Piloo Mody, is known for his wit and humour and I respect him for it; but I think this time it has gone astray.

SHRI BANERJEE has talked about the PTI's functioning and about the setting up of a corporation on the lines suggested by the Press Commission. I can only assure him that we are looking into it.

So far as Shri Piloo Mody's concern or anxiety about the decreasing freedom and erosion of freedom is concerned, naturally, Shri Piloo Mody and myself cannot agree on many things and one such thing is this, because Shri Piloo Mody's concept of freedom is *laissez faire* society.

SHRI PILOO MODY: Question.

SHRI I. K. GUJRAL: He may have his own reasons for doing it. But his anxiety has grown, since nationalisation, more. I do not know whether the voice of Shri Piloo Mody should prevail or whether the voice of an overwhelming majority represented in this House should prevail. I can only assure him that freedom is not only eroding but freedom is expanding itself and a new content is being given to it.

MR CHAIRMAN: I shall now put amendments Nos. 1 and 2 moved by Shri Shiva Chandra Jha, to the vote of the House.

*Amendments Nos. 1 & 2 were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 2 was added to the Bill.*

**Clause 3**— *(Repeal and Saving)*

**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** (भिंड) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1969 के पृष्ठ 2 पर धारा 3(2) को विधेयक में से कम कर दिया जाए। (5)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर चीज का इलाज अध्यादेश नहीं होना चाहिए। अध्यादेश का महत्व तभी ोता है जब किसी महत्व के अवसर पर महत्वपूर्ण कारण होने पर ही उसे जारी किया जाए। इस समस्या का अगर निदान खोजना है तो कारणों में हम को जानना होगा और कारण ढूंढ कर उनको दूर करना होगा। अध्यादेश हर चीज का इलाज नहीं होता है। शासन इसे गंभीरता से सोचे।

अगर आप सचमुच फ़्रीडम आफ प्रेस में हैं तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। हर कीमत परप्रेस की स्वतंत्रता को कायम रखा जाना चाहिये। यह चीज़ कथनी तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसको आपको अमल से भी सिद्ध करना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब शासकीय सूचना प्रसारण विभाग में समाचार पत्रों के लिए काली लिस्ट और व्हाइट लिस्ट जो आपने बना रखी है, उनको खत्म कर दिया जाए। अलग अलग ढंग से सूची बनाना बन्द होना चाहिए। इस का आधार यह न हो कि गवर्नमेंट की नीतियों या गवर्नमेंट में बैठे हुए व्यक्तियों का प्रकाशन कौन सा पत्र किस तरह से कर रहा है। अगर आपने इसको ही आधार माना तो प्रेस की स्वाधीनता नहीं रह पाएगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो छोटे पत्र हैं अगर सचमुच में उनको हर तरह से सहयोग नहीं दिया गया, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया गया तो प्रेस की स्वाधीनता नहीं रह सकेगी।

**श्री विभूति मिश्र** (मोतिहारी) : प्राइवेट प्रेस एजेंसीज़ जो हैं ये जब किसी एम्लायी को चाहती हैं निकाल देती हैं और जिस को चाहती हैं रख लेती हैं। इन के यहां कोई हिसाब किताब नहीं है। यह प्राइवेट सैक्टर की दिक्कत है। उधर के भाई कहेंगे कि मैं प्राइवेट सैक्टर की शिकायत करता हूं। लेकिन प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर में एक फर्क तो है। पब्लिक सैक्टर किसी आदमी को निकाल हीं सकता है, छोटे से छोटा चपरासी भी जो है, उसको भी निकाल नहीं सकता है, उसकी भी राष्ट्रपति तक पहुंच होती है, उन तक जाने का वह हक रखता है, उससे रोजी रोटी आसानी से नहीं छीनी जा सकती है। लेकिन ये जो प्रेस एजेंसीज हैं या प्रेस वाले हैं ये जिस को चाहते हैं रख लेते हैं और जिस को चाहते हैं हटा देते हैं। इस वास्ते हम लोग चाहते हैं कि सारी चीज पब्लिक सैक्टर में आए ताकि लोगों को अपनी रोज़ी रोटी कमाने में सहूलियत हो। जब तक ये प्रेस एजेंसीज़ या छापे खाने पब्लिक सैक्टर में नहीं आ लेते हैं तब तक इनके जो एम्प्लायी हैं उनकी नौकरी की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए। यह काम आप शीघ्रातिशीघ्र करें। इतना ही मुझे आप से निवेदन करना है।

SHRI I. K. GUJRAL: Mr. Chairman, Sir, hon. friend has mentioned about advertisements to small and medium newspapers. To some extent, I have already deal with the problem. In a minute, I would like to say only this thing that there has been increasing percentage of advertisements to small and medium newspapers. In 1966-67, small and medium newspapers were getting 40.1 per cent; in 1967-68, it rose to 45.88 per cent and in 1968-69, it rose to 51.6 per cent. We are now going to increase the percentage further.

So far as the black-list mentioned by my hon. friend is concerned, I can only assure him that there is no

(Shri I. K. Gujral.)

such thing as black-list There is only a small and a very brief list of some newspapers who again and again indulge in communal propaganda and it is only those newspapers which are habitual offenders for spreading hatred between various communities that are not given advertisements. Everybody else is given advertisements.

SHRIMATI ILA PALCHAUDHURI (Krishnagar): I hope, the hon. Minister will put the paper *Organiser* on the black-list. It is a communal paper. It forments communal troubles and writes most horrible things personally against the highest in the lond.

SHRI I. K. GUJRAL: I would only say this that the names of people or papers on th list who are barred from receiving advertisements is not made public. I hope my hon. friend will not press me for that.

So far as the point made by my hon. friend, Shri Bibhuti Mishra, is concerned, we are very much about it. We do feel that an essential ingredient of the freedom of press is that the working journalists should be secured of their jobs. I mentioned the other day in my speech that the appointment and security of working journalists from editor downwards should be secured in such a way that the owner does not have much say in it because the freedom of press can only be secured if the appointment, the security and the working conditions of working journalists and editors are out of the powers of those moneyed people who want to pressurise them.

MR. CHAIRMAN: Now, I put Amendment No. 5 of Shri Kushwah to the vote of the House.

*Amendment No. 5 was put and negatived*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 3 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 3 was added to the Bill.*

*Clause* v, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI I. K. GUJRAL: While requesting you to ask the House to pass the Bill, I want to make an important....

SHRI MADHU LIMAYE: Announcement?

SHRI I. K. GUJRAL: Not announcement. I want to make an important point because here again and again points have been made regarding the intervention or the proliferation of the foreign money in press and often have we dealt with this point both in reply to questions and also in reply to debates. I have been feeling that perhaps we have not been able to tell the House sufficiently and, therefore, I would like to use this occasion to give some more information on this point.

You would recall that the Home Minister, while speaking in this House on 14th May, 1969, regarding use of foreign money in the last General Elections, had made one or two points which are relevant today are—I quote the Home Minister.

> ....that the Government propose to bring forward a comprehensive legislation to impose suitable restrictions on receipt of funds from foreign organisations, agencies or individuals otherwise than in the course of ordinary business transactions...."

The Home Minister had also gone further and made a point that:

> "....special cells are being created in the Intelligence Bureau and the Directorate of Enforcement in the Ministry of Finance for undertaking closer scrutiny of remittances, conversions, etc., of foreign currency to discourage the clandestine foreign financial assistance."

We, in this Ministry, have also been concerned about it. Therefore, Government has undertaken a study as to how much influence does the foreign money have on our press and its freedom. Some of the directions towards which our inquiry is proceeding are: (1) the amount of newsprint imported into this country by various embassies, the amount actually used by them for their own publications and the disposal of the remainer, whether by way of gift, subsidised sale, loan, etc; (2) printing presses used by embassies, etc., of various countries, the prices paid by them forp printing work, whether these include an element of subsidy and what is the explanation of the subsidy; (3) the functioning of various newsagencies, Indian and foreign, operating in India. whether they are free or subsidised, and the existence of any links between them *inter alia* and|or with foreign government or foreign organisations; (4) the trips in India and outside made by journalists at the expense of foreign countries or organisations, whether they are financed by independent trusts or agencies or otherwise, whether these trips are on an exchange basis; (5) whether any newspaper or journal received or receives direct subsidies from froeign countries or organisations and|or whether they get payments from undisclosed or not easily traceable sources; (6) whether any Indian journalist earned large sums by sending despatches abroad, whether these are paid for at normal rates or whether any journalists receive retaining fees which are unusually high; (7) whether large numbers of newspapers or journals printed in ndia ae bought in bulk by foreign interests; and (8) whether any other kind of subsidy, direct or indirect is paid on a significant scale to any newspaper, journal or journalist by foreign interests.

This is the direction along which we are proceeding to make our preliminary enquiries. Once we have completed our preleminary enquiries, our approach is, after the *prima facie* facts have been obtained, to ask the Press Council, or with the advice of the Press Council, to institute an open inquiry into all these factors so that the freedom of press can be really granted. This is the direction in which Government has been proceeding since May-June this year, and I hope, I have the support of the House in this.

I move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill be passed."

SHRI JAIPAL SINGH (Khunti): Mr. Chairman, Sir, I regret I must oppose the passing of this Bill. I wish to restress again that this Bill should have been brought first before this House. My reason is very obvious. The Chair has given the ruling and I accepted the ruling because, according to me, the throne is greater than the man. Even if the Chair, in my opinion is off the track once the ruling is given, I accepted it. Mr. Bhandare, who is supposed to be one of the experts, in Rules of Procedure, supports me in my views. It is very clear that any involvement on the Consolidated Fund of India must originate here. It is a very serious incursion into our authority as Lok Sabha where every money bill has to be passed before it goes to the Council of States. They may say 'Yes' or 'No', but the ultimate authority rests on us. But now this Bill involves something like—the hon. Minister may say whether it is Rs. 20,000 or Rs. 2 lakhs—even if it is half a paisa, it cannot originate in the Council of States.

The second point is that he mentioned that a second Press Commission would be appointed. Sir, I was a member of the First Press Commission and they promised on the floor of the House that they had accepted all our recommendations,

[Shri Jaipal Singh.]

and now he says that it will take some time to implement them. Will it be on doomsday? Now the Second Press Commission's recommendations will come. It will take another hundred years. By that time we will not be here.

Sir I oppose this Bill on the technical issue; otherwise support my hon. friend.

SHRI E. K. NAYANAR (Palghat): Sir, the Minister, while replying has said that he is giving more advertisement to the regional papers. The percentage of advertisements given to the medium size papers varied from 14.10 to 51.6 per cent in 1969. So far as our regional language papers are concerned, the Government is not supporting them. They are supporting those papers who are supporting the Government.

So far as our state of Kerala is concerned, more than 20 daily papers are running and the papers supporting the Central Government get more advertisements and other facilities. Not only that, the monopoly press—the Goenkas and Dalmias—are now getting more advertisements. From my own experience, medium size papers are not getting encouragement. My experience is that in the last few years we do not get any advertisements from the Central Government. We have just now written to the Minister. Now they are thinking over it. The monopoly press are controlling not only the industry but they are trying to mould public opinion. Those who are opposed to monopolies and propagate against them are maligned and people are confused.

Sir, Government must help the medium-sized and the regional language papers. What happens is, English papers get more advertisements. Regarding the regional language papers, the hon. Minister has not stressed that point at all. Hindi papers get more advertisements. We are not against that. But we request that all the other regional papers in Malayalam, Tamil Telugu, etc. should also get more encouragement. Teleprinter facilities should be given to these regional newspapers. The monopolistic control of the press must be ended.

Sir, the Employees Federation has demanded for that. Some of the hon Members who spoke on this Bill have also accepted that demand, that the monopoly control of the press must be ended.

We find some of the monopolists are not only controlling the papers, but also discharging the employees and appointing them as they like. Those who are not supporting them are being removed or dismissed.

Therefore, Sir, our demand is that the regional language papers must get more aid and facilities and encouragement. Government must take stringent measures against the monopoly papers. I want encouragement and newsprint facilities and advertisements also to be given to the regional language papers and also teleprinter service. The Minister has not replied to this question relating to regional papers. They do deserve more facilities, encouragement and help from the Government.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति जी, अभी मंत्री महोदय ने जो कहा कि फ्रीडम आफ प्रेस होना चाहिए, इस को कोई आदमी मतभेद नहीं रख सकता । लेकिन जो आप कहते हैं उसे आप कितना करते हैं, यह सवाल है । पिछले चार पांच महीने से जिस तरह से अखबारों का ट्रेंड हम देख रहे हैं एक निश्चित प्लान और पहले से नियोजित प्लान, एक सिस्टेमेटिक तरीका चल रहा है उनका गला घोटने का और परिणाम यह हुआ है कि कम से कम दिल्ली के अखबार चार पांच महीने से ड्रिफ्ट करते जा रहे हैं एक खास रुख की तरफ और उसकी जिम्मेदारी सरकार पर है, उस से सरकार बच नहीं सकती । मैं

यह कहूंगा मंत्री महोदय से कि आज आप जो परम्पराएं डाल रहे हैं, जब से विशेषकर आप इस के मंत्री बने हैं, वह इतनी खतरनाक परम्परा है, आज आप हैं, कल को दूसरा भी हो सकता है, वह भी इसी तरह से चलेगा और प्रैस के फ्रीडम के नाम से उस पर स्टेट कंट्रोल हो जायगा जो कि और अधिक भयानक है। मैं यह मानता हूं कि प्रेस पर कुछ पूंजीपतियों का कब्जा है और वह अच्छा नहीं है। उसका कुछ हल निकालना चाहिए। लेकिन क्या यह जवाब है कि उस पर स्टेट कंट्रोल हो? उस का यह जवाब नहीं है। उस का जवाब कुछ और होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए, उसके लिए आप यह प्रेस कमीशन बिठा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उस को यह रिफर कर दिया जाय और वह मालूम करे। स्टेट कंट्रोल भी उतना ही खराब है जितना कि पैसे वालों की मोनोपली है। मेरा कहना यह है कि आप इस को एन्क्वायरी करा सकते हैं, इम्पार्शियल एन्क्वायरी कराएं कि पांच छः महीने से क्या यह सही नहीं है कि दिल्ली के जो प्रेस हैं वह एक तरफ को ड्रिफ्ट करते जा रहे हैं? क्या यह सही नहीं है कि प्रधान मंत्री का एक अधिकारी, जो उन का प्रमुख पब्लिसिटी आफिसर है वह एक प्रमुख अखबार का यहां पर सम्पादक बन गया है? और अखबार के मालिकों के खिलाफ कुछ एन्क्वायरी होने वाली है, उस को एक छोटी मोटी एन्क्वायरी कर के दबाने की बात की जा रही है और उस बहाने से उस को एडीटर बनाया गया है? क्या यह फ्रीडम आफ प्रेस है?

**सभापति महोदय** : गुप्ता जी, एक बात सुनिए। जरा बैठ जाइए। यह जो चार्ज है किसी के ऊपर यह बराबर रखते जा रहे हैं, उस दिन मैं ने नियम कोट किया था कि अगर इस तरह का चार्ज किसी के खिलाफ है जिस का जवाब देने वाला मौजूद न हो तो उस को पहले आप लिख कर भेजिए।

**एक माननीय सदस्य** : वह नाम नहीं ले रहे हैं किसी का।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : एक चार्ज यह आया कि टाइम्स आफ इंडिया के बोर्ड की बदली के बारे में आप उन को कुछ सुविधाएं देना चाहते हैं और उसके बदले में टाइम्स आफ इंडिया प्रधान मंत्री के हक में लिखे यह आप कुछ उन के साथ सौदा करना चाहते हैं। यह भी अखबारों में आया क्या स्टेट्समैन के ईरानी से आप नहीं मिले? उस ने अखबार में छापा, उससे आप मिले और आप ने उस से कहा कि आपके इस इस तरह के लेख होने चाहिए और प्रधान मंत्री को आप को सपोर्ट करना चाहिए। तो अब अगर प्रधान मंत्री महोदय ......... (व्यवधान) ..... सभापति महोदय, उस में जो कार्टून आते हैं, मैं तो स्टेट्समैन खरीदता ही हूं, कार्टून देखनेके लिए मुझ तो इतने पसन्द हैं उस के कार्टून कि मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में मोस्ट लीडिंग कार्टूनिस्ट वही है और उसके बारे में प्रधान मंत्री कुछ कहें यह उनको शोभा नहीं देता। मैं समझता हूं कि इस तरह से एतराज़ करना और एक प्रधान मंत्री इस तरह की बात करें यह गलत है। आखीर में अखबार को लोगों को एजूकेट करने का काम करना होता है। लोग ठीक रास्ते पर जाएं यह इस का मतलब होता है। केवल किसी एक व्यक्ति की चाहे वह प्रधान मंत्री हो या सरकार हो या आप हों या मैं होऊं, किसी की ढोल पीटना यह उसका उद्देश्य नहीं होता ह।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी आप ने कहा कि आप 55 परसेंट एडवर्टाइज़मेंट जो देते हैं वह भारतीय भाषाओं के अखबार जो हैं उन को देते हैं। लेकिन अंग्रेजी जानने वाले केवल डेढ़ परसेंट हैं, उन को आप 45 परसेंट एडवर्टाइज़मेंट देते हैं। आप अगर भारतीय भाषाओं के अखबारों को एन्करेज करना चाहते हैं तो केवल सर्कुलेशन से एडवर्टाइज़मेंट मत दीजिए। आप उनको एन्करेज करने के लिए ताकि वह सस्ते हों,

[श्री कंवर लाल गुप्त]

अच्छे हों, इसलिए ज्यादा उन का एक कोटा तय कर ीजिए कि अंग्रेजी के अखबारों को केवल दस परसेंट मिलेगा और 90 परसेंट भारतीय भा ाओं के अखबारों को मिलेगा । अब यह परम्परा हो गई है अखबारों में, खास तौर से बड़े बड़े अखबारों में कि उन में एडवर्टाइज़मेंट ही एडवर्टाइजमेंट होता है और उसका नतीजा यह होता है कि अखबारों में खबरें बहुत थोड़ी आती हैं ।उस पर भी कुछ कंट्रोल सरकार को करना चाहिए । अभी जो ऐडवर्टाइज़मेंट का रेशियो है वह शायद 40 परसेंट आता है , वह 40 परसेंट बहुत ज्यादा है । मैं समझता हूं कि एडवर्टाइज़मेंट पर एक लिमिट होनी चाहिए और अगर वह लिमिट ज्यादा करते हैं तो उस का लाभ रीडर्स को मिलना चाहिए । आप उन को मजबूर करें कि वह उसकी कीमत फिर कम करे ताकि पढ़ने वालों को फायदा हो । नहीं तो एडवर्टाइज़मेंट से भी रीडर्स को नुक्सान होता है और उन को खबरें भी कम मिलती हैं ।

आखीर में, जो फोरन फंड्स के बारे में आप ने कहा उस के बारे में कह कर मैं समाप्त करूंगा । आप ने कहा कि फोरन फंड्स के बारे में होम मिनिस्टर साहब कुछ कर रहे हैं । दो साल से यह चल रहा है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ । उन्होंने कहा कि वह अपोज़ीशन लीडर्स से बातचीत करेंगे लेकिन अभी तक उन्होंने अपोजीशन लीडर्स से बातचीत भी नहीं की । मैं ने पैट्रियट और लिंक के बारे में सवाल उठाए थे कि उन्हें विदेशी सहायता मिलती है । मुझे यह मालूम है कि सी बी आई ने एन्क्वायरी की है और यह साबित भी हो गया है कि उन्हें पैसा बाहर से मिलता है । लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । तो इस तरह से दो साल तक गवर्नमेंट का इनडेसीशन रहे यह बहुत गलत है । मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जल्दी कार्यवाही करें और ऐडवर्टाइज़मेंट की पालिसी, न्यज़प्रिन्ट की पालिसी और लोन की पालिसी अच्छा यह होगा कि सरकार अपने हाथ में न ले, प्रेस कौंसिल को दे ताकि प्रेस कौंसिल के लोग देखें कि कब किस को मदद देनी है, किसको न्यूज़प्रिन्ट देना है, कितना देना है, नहीं तो स्टेट कंट्रोल मोनोपली का जवाब नहीं होगा । उससे डिक्टेटरशिप का ट्रेन्ड बढ़ेगा । वह हो सकता है कि आज टेम्पोररी आप को लाभ दे लेकिन देश के हित में वह नहीं होगा ।

**श्री अर्जुन सिंह भदोरिया** (इटावा) : सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान समाचार भारती समाचार एजेंसी में उत्पन्न गड़बड़ी और उसमें जानबूझ कर बरती जाने वाली धांधली की ओर विशेष तौर से आकर्षित करना चाहता हूं । आज बहुत से अखबार तो पुंजीपतियों के या कुछ गुटों के हैं परन्तु "समाचार भारती" एजेंसी इसमें अधिकतर पैसा राज्य सरकारों का और केन्द्रीय सरकार का लगा हुआ है । जहां तक मुझे जानकारी है अकेले उत्तर प्रदेश राज्य का 5 लाख, बिहार का 5 लाख, राजस्थान का 5 लाख, मध्य प्रदेश का 5 लाख, गुजरात का 5 लाख और मैसूर का एक लाख और केन्द्र ने भी अपना बहुत कुछ पैसा इसमें हिस्से के रूप में लगाया है । लेकिन इन राज्य सरकारों की तरफ से उनका एक भी प्रतिनिधि उसमें नहीं है । मेरा सुझाव है कि राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार का भी प्रतिनिधि इसमें बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में रहे । मैं आश्चर्य में हूं कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के जो अध्यक्ष हैं, वर्ष में एक भी मीटिंग में शामिल नहीं हुए । नतीजा यह है कि दूसरे जो लोग उसमें हैं जिस ढंग से चाहते हैं उस ढंग से संचालन करते हैं । मेरा सुझाव संक्षेप में यह है कि इसकी देखभाल की जाय, साथ ही साथ इसमें उत्पन्न गड़बड़ी की शीघ्र जांच की जाय और

जांच के बाद तुरन्त एक्शन लिया जाय, क्योंकि 15 लोगों को बिना किसी कारण के निकाला गया है, ऐसे लोगों को जो बीमार थे, उनकी बीमारी की जाच भी की गई और पता लगा कि वे मेडिकल इंस्टीचूट में हैं, उसके बावजूद भी उनकी छुट्टी कैन्सिल की गई, उनको तबदील किया गया, उनको बरखास्तगी के नीटिस दिये गये। इस तरह से अगर समाचार पत्रों और समाचार एजेन्सियों के लोगों के सिरों पर धमकी की नंगी तलवार टंगी रहेगी तो वे बेचारे अपने सुविवेक से काम नहीं कर सकेंगे। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और अपराधी अधिकारियों के विरुद्ध वैधानिक कदम उठाये।

**श्री अब्दुलगनी डार** (गुड़गांव) : सभापति जी, जब मैं अपने भाई जार्ज को सुन रहा था तो मुझे ख़याल आया—

की मेरे कत्ल के बाद उस ने जफ़ा से तोबा,
हाय इस जूदे-पशेमां का पशेमां होना।

सारी उम्र यह चर्चा करते रहे कि अखबार सरमायेदारों के हैं, उनके हाथ में नहीं रहने चाहिये, इस तरह से वे देश का नुकसान करेंगे—आज अगर इन्दिरा जी उससे फायदा उठाती हैं, तो उनको उठाना चाहिए। 75 परसेन्ट वोट इन्होंने गिरी को दिये, लेकिन वह कहती हैं कि हम जीत गये . . . (**व्यवधान**) . . . अरे भाई, मैं यही तो अर्ज़ करने वाला था कि सारी उम्र सोशलिज्म की चर्चा करते रहे . . . .

**श्री महाराज सिंह भारती** (मेरठ) : रेड्डी हार गये तो अब आप उस हार को रिकन्साइल कीजिये, गिरी साहब जीते हैं, तो इससे बिदकते क्यों हैं।

**श्री अब्दुलगनी डार** : भारती जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि आप इलेक्शन जीते हैं, हम हारे हैं। मेहरबानी कर के मेरा वक्त जाया न कीजिये, मुझे अपनी बात रखने दीजिये। जब सरकार आपकी तरफ आती है, आपकी बात को मानती है. तब तो आप को इसकी तारीफ़ करनी चाहिये, इसकी मदद करनी चाहिये, क्योंकि वह आपकी बात मानती है। आप सोशलिज्म चाहते थे . . .

**श्री मधु लिमये** : कहां मानती है। वह टाइम्ज आफ़ इण्डिया जैन साहब को दे रहे हैं, मैं कहता हूं कि ऐसा न करो—कहां मानती है ?

**श्री अब्दुलगनी डार** : एक खराबी करती है तो उस खराबी का इलाज करो . . .

**सभापति महोदय** : आप चेयर को एड्रेस कीजिये।

**श्री अब्दुलगनी डार** : सभापति जी, एक खराबी हुई है, मैंने भी इसका उन से जिक्र किया, मुझे इसका सब से पहले पता चला। लेकिन इस पर मैं गुस्सा नहीं करता क्योंकि जो खराबी है, वह आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जायगी।

मैं विभूति मिश्र जी से नेशनल हेरल्ड की बात कर रहा था—वह जनहित निधि का अखबार है, वह भी खुदा की कस्म सरमायेदारों के लाखों रुपयों से चल रहा है . . .

**एक माननीय सदस्य** : नहीं।

**श्री अब्दुलगनी डार** : लाखों रुपया जनहित निधि को दिया गया है, अगर आप चैलेंज करें तो मैं साबित कर सकता हूं कि करप्ट मिनिस्टरों और करप्ट आदमियों ने दिया है।

आखरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं—गुप्ता जी ने कहा कि अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे बहुत कम लोग हैं, लेकिन हमें अपने साउथ वाले भाइयों को हर हालत में अपनाना चाहिये, हम उन के साथ चलना चाहते हैं, उनकी इज्जत भी करना चाहते हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं हिन्दी के अखबारों

[श्री अब्दुलगनी डार]

को एडवर्टिजमेंट कम मिलना चाहिये और बाकी अखबारों को ज्यादा मिलना चाहिए। जब गुजराल की जगह मेरी बहिन इन्दिरा इस महकमे में मिनिस्टर थीं तो मैने एक सवाल किया था। उस वक्त उन्होने बतलाया था कि देश में इस वक्त सब से ज्यादा अखबार— चाहे साउथ हो, ईस्ट हो, नार्थ हो या वेस्ट हो— उर्दू जुबान में निकलते हैं, लेकिन इन्होंने उर्दू जुबान को सिर्फ 2 परसेन्ट दिया है। जिसके अखबार आज भी मुल्क में सब से ज्यादा निकलते हैं और उनके छापने वाले हिन्दू हैं, मुसलमान नहीं हैं . . . .

**श्री मधु लिमये** : इस में हिन्दू मुसलमानों का कोई सवाल नहीं है।

**श्री अब्दुलगनी डार** : जो भी निकालते हैं, उस वक्त इन्दिरा जी ने अपने जवाब में बताया था कि इन को सिर्फ 2 परसेन्ट मदद देते हैं। जिसके लिये गांधी जी ने कहा—हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी। सभापति जी, मैं चाहता हूं कि हिन्दी सब से उत्तम रहे, वह हमारी कौमी जुबान है लेकिन हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी . . . (व्यवधान) . . .

**सभापति महोदय**: अब आप बैठ जाइये।

**श्री अब्दुलगनी डार**: सभापति जी, मैं सिर्फ इतना ही याद दिलाना चाहता हूं कि यह तो अपनी अपनी किस्मत है—एक की किस्मत में खुशी है, वह खुश है, लेकिन इन की किस्मत में तो रंज लिखा है, इसलिए ये रंजीदा हैं। सोशलिज्म में इनकी जीत हुई है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हम हार गये।

**श्री मधु लिमये** : हम हारे नहीं हैं, हम लोग तो जीत गये हैं।

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI (Howrah): Some hon. Members criticise monopoly in the economic sphere. But, at the same time, they want to monopolise the time of the House. So, the growth of monopolistic tendencies are evident in every sphere of our national life and press is no exception. The press barons are today thinking of utilising their power through the press to monopolise views of the people in their favour. I am very glad that the hon. Minister has very boldly and courageously stated that he will be preserving the freedom of the press. But, in the present atmosphere of the country, I am not quite sure whether a guarantee of this kind of freedom to the press will be for the good of the country, because the press barons have been utilising the machinery of the press in such a manner as to serve only their own interests.

I will cite only one example. During the presidential elections I had the privilege of issuing a statement. News agencies like PTI and UNI circulated it to all the papers. One of the English papers of Calcutta published an entirely different version of that statement which has injured my reputation tremendously in the constituency which I represent. I am referring to the *Ananda Bazar Patrika* of Calcutta. I tried to bring a privilege motion and the Speaker has kindly agreed to write to the Editor to find out the facts.

What I say is that these things cannot be equated with the freedom of the press. Freedom of the press connotes that the machinery of the press would be utilized in such a way as to bring in some benefit to the people. Unfortunately, whenever any progressive measure has been taken by the government, all the powerful press have expressed their views against that move and tried to propagate before the people that such measures would be detrimental to the interests of the people. Therefore, I think complete freedom of the press would be negation of the freedom of the people of the country. So, I would request the hon. Minister to

consider how far he should allow the freedom of the press to be watch-word today.

The appointment of the Press Commission is a necessity today because the recommendations of the First Press Commission are obsolete now in view of the new direction in which the country is developing. Therefore, not only should a Press Commission be appointed immediately but its terms of reference should be so wide that the Press Commission could go into the working of the press for the benefit of the people and recommend how the press can be mobilised to serve public and the country.

**16 hrs.**

**श्री शिवनारायण** (बस्ती) : अध्यक्ष महोदय, प्रेस को देश में चौथी स्टेट कहा जाता है। डिमोक्रेसी में प्रेस का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है । हमें प्रेस को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए । हमको आशा है कि बहुत निष्पक्षता के साथ इस देश में प्रेस की तरफ से सही क्रिटिसिज्म होगा । चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या कोई आर्डिनरी सिटिजन हो, सभी को इक्वल शेयर मिलना चाहिए – प्रेस कमीशन से मेरी यह अपील है । हमारी डेमोक्रेसी इसी पर बेस करती है । चाहे सरकार की मशीनरी हो, चाहे विरोधी दल हो या कोई और – प्रेस ही डिमोक्रेसी में जज होता है । मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट प्रेस के साथ इक्वेलिटी का बर्ताव करे, किसी भी प्रेस के साथ भेद भाव नहीं होना चाहिए । अंग्रेजी की बड़ी चर्चा हुई है लेकिन इस देश के केवल डेढ़ परसेंट आदमी ही अंग्रेजी जानते हैं । उनके लिए तो इतना पैसा खर्च कर दिया जाय लेकिन देशी भाषा वालों के लिए वह नहीं किया जाता । मैं डा० त्रिगुण सेन को बधाई देता हूं कि उन्होंने कहा कि इस देश में शिक्षा अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, वह चाहे तेलगु हो या मलयालम हो, उर्दू हो या हिन्दी हो,लेकिन अपनी भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए । अभी मेरे बुजुर्ग ने उर्दू की बात कही, मैं उनका समर्थन करता हूं उर्दू भाषा पंजाब, हैदराबाद, दिल्ली में हिन्दू लोगों में भी चलती है । इस हिन्दू उर्दू के झगड़े में अंग्रेजी हमारी छाती पर चढ़ रही है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर उर्दू है तो उसमें कोई गुनाह नहीं, हिन्दी, मल्यालम, बंगला कुछ भी रहे उसमें कोई गुनाह नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह सरकार निष्पक्षता के साथ, नेकनीयती से और सम भाव से हरएक को देखे जिससे सरकार के ऊपर गन्दा क्रिटिसिज्म न हो । प्रेस चौथी स्टेट होती है । उसको पूरा राइट होना चाहिए कि वह इस गवर्नमेंट की सही पिक्चर दुनिया को दे । रोजाना यहां पर सवाल आते हैं कि उसको इतना पैसा मिला, उसको इतना पैसा मिला । मैं चाहता हूं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो । मुझे उम्मीद है कि प्रेस कौंसिल ठीक प्रकार काम करेगी । धन्यवाद ।

**श्री शशि भूषण** (खारगोन) : सभापति महोदय, जो फ्री एन्टरप्राइज की बात करते हैं वही फ्री प्रेस की बात करते हैं । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की जो सही पालिसीज हैं उनके लिए किसी इश्तहार की जरूरत नहीं है । अभी जैसे बैंक नेशनलाइजेशन हुआ उसके लिए किसी इश्तहार की जरूरत नहीं है । अच्छा हो कि बड़े अखबारों को इश्तहार न दिये जायें बल्कि छोटे अखबारों को ही दिये जायें। बड़े अखबारों को उनकी परवाह भी नहीं है क्योंकि उनके पास वैसे ही काफी रुपया है । उनके पास काफी ब्लैक का रुपया है। आप लीफलेट्स और पैम्फलेटस छपवाइये और उनका सीधा सम्बन्ध देश की जनता से स्थापित किया जाये, इस देश के 30 लाख शिक्षकों के द्वारा बजाये इसके कि उसके लिए आप इन सफेद हाथियों को पैसा दें । बस इतनी ही मेरी प्रार्थना है ।

**श्री मधु लिमये** : मेरा सवाल सिर्फ यही है कि दो तीन रोज पहले जब टाइम्स

[श्री मधु लिमये]

आफ इंडिया का मामला उठा था तो हमने पूछा था कि क्या यह बात सही नहीं है कि उद्योग विकास मंत्री और कानून मंत्री ने कैबिनेट के फैसले के अनुसार फाइल में नोट किया कि तीन डायरेक्टर साहू जैन गुट के हो जायेंगे और उनमें से उनके सुपुत्र अशोक जैन उसके चेयरमैन बनेगें – क्या मंत्री महोदय आज इस बात का कोई जवाब देगें कि इस तरह का निर्णय हुआ है या नहीं और फाइल में नोटिंग है या नहीं ? प्रेस की जो स्वतंत्रता का सवाल है वह इससे जुड़ा हुआ है।

SHRI I. K. GUJRAL: Sir, some friends, including Shri Jaipal Singh, have mentioned about the recommendations of the Press Commission. I have already said that so far as the recommendations of the Press Commission are concerned, if anybody would pursue in detail the Press Commission's report, he would come to the conclusion that most of the recommendations have already been implemented. Only one or two, or perhaps three, remain still to be implemented. As a matter of fact, even the concept of the Press Council itself, for which a Bill is being brought forward, is a recommendation of the Press Commission. Therefore to say that we have not implemented the Press Commission's recommendations is not correct.

About advertisements, there must be some misunderstanding. I think, that is a misunderstanding in the concept of it. Let me clarify here that the DAVP advertisements are not a subsidy. They are not meant to give support in the direct sense or to subsidise newspapers. It is a Governments advertisement programme for its various projects. For instance on family planning programme, we spend a considerable amount of money for making the family planning movement popular. Therefore, while releasing the advertisements, while certain things like the language papers, small and medium newspapers have to be kept in mind, we have also to keep in mind what would have more leadership pull. Therefore, it is not possible to have the DAVP policy from the point of view of subsidising certain sections. It is only that a certain message has to be put across to an audience for which the advertisements are used. We are helping small and medium newspapers in this programme also not only because we want to help them but because a very high percentage of readership is commanded by small and medium newspapers.

Some hon. Members made a point that the DAVP advertisements should be released by the Press Council or somebody else. That is not possible. That is a Government's advertising programme. The Government has to decide what type of programme it will put forward, in which area it will put forward and what audience it wishes to address.

Then my hon. friend Shri Kanwar Lal Gupta, having made his point has unfortunately left. It is not fair to me. I would only say that he talked a great deal about the freedom of press. Yet, the interesting thing is that it comes from a party which basically does not believe in any freedom. . . .

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI (Bhopal): Who told you that? I challenge the statement. He says, we do not believe in freedom. What does he mean? We cannot allow him to level false charges against our party. We believe in freedom. (*Interruption*).

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh): He is making a false allegation I cannot permit him. (*Interruptions*).

SHRI I. K. GUJRAL: He says, he cannot permit me to say my words.

How much freedom will he permit others?

The main point is this. I am saying it repeatedly that this party does not believe. (*Interruptions*). This is the freedom, he permits.

SHRI SHRI CHAND GOYAL: He is making a false allegation. **(*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: You withdraw that.

SHRI SHRI CHAND GOYAL: I will not withdraw. He is making a false allegation. He is maligning our party...... (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: You please withdraw that. आप इसको विदड्रा करने के तैयार है या नहीं ?

**श्री श्रीचन्द गोयल :** जी नहीं ।

**सभापति महोदय :** आप नहीं विदड़ा करते ह तो हाउस से चले जाइये । यह एक्सपंज कर दिया जाये ।

**श्री मधु लिमये :** यहां पर निर्णय हो चुका है कि अगर यह शब्द कहा जायेगा तो वह रिकार्ड में नहीं रहेगा ।. . . (**व्यवधान**) .

**श्री शशि भूषण :** यह शब्द जिनको प्रिय है वह उसे अपने पास रखें ।

**श्री मधु लिमये :** स्पीकर साहव ने निर्णय दे दिया है कि यह शब्द रिकार्ड में नहीं रहेगा ।

MR. CHAIRMAN: That will not go on record; that should be expunged.

SHRI I. K. GUJRAL: Then, Shri Kanwar Lal Gupta tried to enunciate the freedom of the Press. I would say that an alternative for monopoly control is not State control. That is not a way out. That will not bring forward the freedom of the press. The freedom of the press as enshrined in the Constitution is our commitment. Therefore, there is no intention whatsoever, either directly or indirectly, to bring in State control. But solutions for various problems have to be sought and I was hoping that Shri Kanwar Lal Gupta would suggest some solutions also. The Press Commission has suggested something and, as I have said, we are taking steps to implement that.

Shri Kanwar Lal Gupta also brought in the appointment of an editor of a particular newspaper. It is not for me here to stand up and justify or criticise the appointments in newspapers which are free in their own sphere to appoint whomsoever they like and dismiss whomsoever they like. But I have said, and I repeat it, that some institutional checks must be brought in, not based so much on the governmental control but on social values so that the appointments of editors, the dismissal of editors, the working conditions of editors, the freedom of editors, all these things, can be guaranteed by the society as a whole. Therefore, all these points can be met only if we come to the conclusion that tence of the control of industrial houses over the press is dangerous for freedom of the press. That is why I am saying this. Let us not only go against this institution, against the industrial houses controlling the press, only when it pinches us or any political party; let us make a commitment on the basis of principle that it is a wrong thing for any industrial house to control a newspaper. Therefore, once we agree that this is wrong, then the solution must be found within our social set-up and our commitments in the Constitution. Within these two frameworks, the Press Commission has tried to recommend certain methods for meeting this, and I can assure the House on behalf of the Government that we are going to implement these.

**Expunged as ordered by the Chair

[Shri I. K. Gujral.]

The point of the *Times of India* having changed the Board of Directors has been brought by my friend Shri Kanwar Lal Gupta; Mr. Limaye also raised this question. Unfortunately, I am not in a position to reply because this is dealt with by the Company Law Department; I am not dealing with this case.

**श्री मधु लिमये** : प्रेस स्वतंत्रता से इस का सम्बन्ध है कि नहीं ?

**श्री इ० कु० गुजराल** : प्रेस स्वतंत्रता से इसका सम्बन्ध इस हद पक जरूर है कि जो इसके मालिक ह वे इस किस्म के हों कि जिनका किसी खास सरमायेदारी से ताल्लुक न हो। मैंने कहा कि हम लोगों का मुकम्मिल विश्वास है कि .

**श्री मधु लिमये** : आप कंस्ट्रक्टिव सुझाव चाहते थे। ने उस दिन भी दिया था कि वकिन्ग जर्नलिस्टस और कर्मचारियों के चार डायरेक्टर लीजिये।

**श्री इ० कु० गुजराल** : आपने टाइम्स आफ इंडिया के मुताबिक पूछा है। मैं यही कह रहा हूं कि में इस पोजीशन में नहीं हूं।

**श्री मधु लिमये** : बाद मैं दीजिये बयान ।

**श्री इ० कु० गुजराल** : क्योंकि मेरा यह महकमा नही है इसलिए अच्छा होगा कि आप उनसे पूछिये जिनका यह महकमा है। वही इस का जवाब दें तो अच्छा हो।

माननीय कंवर लाल गुप्ता जी ने मुझ से एक सवाल किया और मुझ पर एक आरोप लगाया और आरोप यह लगाया कि कोई मिस्टर ईरानी मुझ से मिलने आये और स्टेट्समैन ने मेरे मुताल्लिक लिखा। जहां तक मुझे मालूम है स्टेट्समैन ने ऐसा नहीं लिखा है। उन के अपने अखबार आर्गेनाइजर ने जरूर लिखा यह मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया गया कि स्टेट्समैन के किसी बड़े आदमी से मेंने बात की। स्टेट्समैन के जिस आदमी से मेंने बात की वह खुद कुछ नहीं कहता, बल्कि आर्गेनाइजर कहता है। स्टेट्समैन और आर्गेनाइजर का क्या ताल्लुक है मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर हिम्मत है तो खुद कहें कि मैंने कुछ कहा कि नहीं कहा। माननीय कंवर लाल गुप्त जी इस अखबार के डायरेक्टर हैं, लेकिन उनको अपनी डायरेक्टरशिप का फायदा यहां नहीं उठाना चाहिये। जो ट्रस्ट है उसके वह व्यक्ति हैं। माननीय कंवर लाल गुप्त जी का ग्रुप माननीय बलराज मधोक के ग्रुप से अलग है और माननीय बलराज मधोक के ग्रुप को नहीं पूछा जाता है। एक बात माननीय कंवर लाल जी ने कही कि प्रेस को सब से बड़ा एजूकेट करना है।

I agree with Mr. Kanwar Lal Gupta that the role of the Press is to educate the public opinion, but while educating the public opinion, the press, in its own interest and in the interest of freedom of the press, itself and in the interest of our democratic life, should also keep in tune with the aspirations of the people. Some section of the press tried to go against the stream of the peoples' aspirations in bank nationalisation and, therefore, they realised to their own cost how people react to such a thing . . .

**Shri Bal Raj Madhok:** Ours is a democracy and we accept that there are different parties, different viewpoints. Then what do you mean by one particular point of view? A section of the press may think that it is good and another section may equally rightly think that it is not good. Therefore, why should you harp on the point of people's aspirations? I know, many people feel that it is not a right step, and there are the others who feel that it is a right step. Who is to determine wether it is right or wrong?

**Shri I. K. Gujral:** I have already said and I want to repeat that while

we wish that every section of the press should have freedom to say whatever they wish, the Prime Minister, myself, Mr. Madhok or anybody else, should also have the freedom to differ from a section of the press. Some friend of ours have been very much upset as to why the Prime Minister says publicly that a section of the Press is not behaving.

SHRI BAL RAJ MADHOK: If she says that she does not agree, that is all right. But when she says that the Press is not behaving, it is intimidation. It is not expressing opinion.

SHRI I. K. GUJRAL: The main point again remains. I would like Shri Bal Raj Madhok to give me an opportunity. I use 'behaviour' in the context of social responsibility and that is the concept I am dealing with. I said that the Press has a role to educate within the social responsibility concept.

Now that freedom of the Press obviously Mr. Madhok will agree, does not lead to licence. There should be differentiation between licence and freedom and I am conscious of the fact that even when a section of the Press differs with the national policy on nationalisation of banks, even then I do not think that licence has been used. I am in agreement that the freedom of the Press must be preserved. They should have a right to say whatever they wish to say. As I have said ealier, I will be one man to stand for freedom of the Press at any expense.

About the foreign money, I have already mentioned.

My friend, Mr. Bhadoria, said about Samachar Bharati. Other points I have already dealt with. He has said about the composition of the Board of Directors and that the State Government's representation should be there. I beg to differ with him. Even when Government money is invested, I would not like Government representatives to be on the Board of Directors either of news agencies or of newspapers. Surely, I would like news agencies, as recommended by the Press Commission, should form themselves into public trusts. That would be a better way of functioning. Since Shri Prakash Vir Shastri is sitting here, I hope he will give this his attention and will sense the feeling of the House and will try to take steps whereby Samachar Bharati will give a lead to this country in setting up an autonomous trust composed of leading public men.

My revered friend, Mr. Abdul Ghani Dar, has mentioned about the Urdu Press. I am as much a lover of Urdu as he is. Unfortunately, his figures are wrong. He has said that only 2 per cent of advertisement budget is being given to the Urdu Press whereas the fact is that about 6 per cent of the budget is given to the Urdu Press. Now he should have no grievance.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : प्रताप वीर अर्जुन को आप कितना देते हैं ?

SHRI I. K. GUJRAL: I do not have individual figures with me. If you give me notice, I will let you know. The main point remains.

श्री शशि भूषण : ऐंटी सैक्यूलर प्रेस को क्यों देते हैं ।

SHRI I. K. GUJRAL: I am only saying that it will satisfy Mr. Dar.

My friend, Mr. Chatterji, has posed not given rough treatment which Mr. Dar has mentioned.

My friend, Mr. Chatterji, has posed a point. He said: how far will the freedom of the Press will go. It will go to the fullest extent possible. There is no containment of freedom and there is no dimension or limitation on freedom. Freedom is unlimited. Freedom will go to every extent and this is not a concession or

[Shri I. K. Gujral.]

policy which this Government is pleading. It is enshrined in our Constitution. Therefore, for any one even to think that the feedom of Press should be contained or freedom of Press should have some limitation or there should be some limits on the freedom of Press are very wrong because freedom of Press is a matter of emotional feeling, it is a matter of faith in democracy, it is a matter of faith in our basic freedoms which are enshrined in our Constitution.

I have dealt with all the points. The only point which I have not dealt with is the point raised by Shri Kanwar Lal Gupta. Shri Gupta has lapsed into wisdom and has recommended that he would like some sort of a price page schedule to be brought in. I hope when we bring a Bill to that effect, he will stand up and support it and he will not oppose it. I am repeating it because I have a serious apprehension that he will back out. The only thing I am saying is that I am glad that he has mentioned that price page schedule is necessary. In the reader's interest it is necessary to put some sort of a limitation on the advertisements space. All this will perhaps need a change in the Constitution and I think when I come forward with an amendment of the Constitution, Shri Kanwar Lal Gupta at least alone, if not his Party, will support it.

SHRI BAL RAJ MADHOK: What have you to say about my suggestion regarding the International News Agency of India?

SHRI I. K. GUJRAL: This is a very vital point raised by Shri Bal Raj Madhok. About a News Agency, specialising in international news, I am in total agreement with him. It is under our active consideration because it is very important that not only the news that we get from outside but more so the image of India that is reflected outside must be in our national interest. Sometimes in Asia or Africa or Australia—particularly in Africa and Australia—through some third-party agencies, our image gets deflected. I am in agreement with him and I am very keen that such an agency should come into being very soon.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

---

**16.21 hrs.**

STATUTORY RESOLUTION *RE*. DISAPPROVAL OF BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE AND BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL.

**सभापति महोदय** : अब हम बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल के सटैटुटरी रेजोल्यूशन को लेंगे ।

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh): Sir, I beg to move the following Resolution:

"This House disapproves of the Banaras Hindu University (Amendment) Ordinance, 1969 (Ordinance No. 7 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 17th July, 1969."

काशी विश्वविद्यालय के विषय में जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया है मैं उस के निरनुमोदन के लिए यहां पर खड़ा हूं । सबसे से पहले तो मुझे इस बात का पर आपत्ति है कि सरकार का एक फैशन बन गया है कि अध्यादेश जारी करे । जो लोक सभा का अधिकार है कानून बनाने का उसमें आज सरकार बहुत तेजी के साथ हस्तक्षेप करती जा रही है । 17 जुलाई को यह अध्यादेश जारी किया गया जब कि 21 जुलाई को हमारा वर्तमान सत्र शुरू होने वाला था ।